भारत सरकार

अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 865

बुधवार, 26 जून, 2019 को उत्तर देने के लिए

अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी

865. श्रीमती राम्या हरिदास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधानों से संबंधित सरकारी प्रतिष्ठानों को आमतौर पर लोगों के जीवन की समकालिक विकास संबंधी आवश्यकताओं से जोड़ने के बारे में कोई नीति विकसित और तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या शासन और लोक प्रशासन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों को अपील करने के लिए कोई कार्य पद्धति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री

(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय विकास के लिए और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभ को उपयोग में लाने के उद्देश्य से कार्य करता रहा है। आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु उपग्रह समर्थित आंकड़ों और सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। इसमें टेलीविजन प्रसारण, डायरेक्ट-टू-होम, ए टी एम, मोबाइल संचार, दूरवर्ती शिक्षा, दूरस्थ-चिकित्सा और मौसम, पीड़क जंतु उत्पीड़न, कृषि-मौसमविज्ञान तथा संभावित मत्स्य क्षेत्र शामिल हैं। फसल उत्पादन अनुमान, फसल तीव्रीकरण, कृषि सूखा आकलन, परती भूमि की सूचीबद्धता, भूमिगत जल संभावित क्षेत्रों की पहचान, अंतर्देशीय जलकृषि उपयुक्तता और आपदा जोखिम शमन के लिए भी उपग्रह आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को लाभ पहुंचाता है।

(ख) एवं (ग)

जी, हां। शासन और लोक प्रशासन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष विभाग ने सरकारी विभागों के साथ पूर्व सक्रियता से बातचीत करने हेतु इसरो में विशेषज्ञ कार्यकारी समूहों का गठन किया था और "शासन एवं विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग" पर संयुक्त कार्य योजना तैयार की थी। केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों की भागीदारी से सितंबर, 2015 में नई दिल्ली में आयोजित एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में इन कार्य योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आयोजना, निगरानी एवं निर्णयन तथा आपदा जोखिम शमन जैसे क्षेत्रों में इस सम्मेलन से उत्पन्न परियोजनाओं को पूरा किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार के विभागों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 18 राज्यों में राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया है।

लोक प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को संवेदनशील बनाने हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोगों पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एल बी एस एन ए ए), डी ओ पी टी और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आई एस टी एम), डी ओ पी टी में विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अब तक 1150 से अधिक अधिकारियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है।

***